एक नजर में

मुर्शिदाबाद मे बाबरी मस्जिद बनाने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए : कलेक्टर

मन्दसौर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की स्थापना की घोषणा की गई है। विधायक कबीर ने यहां तक कहा कि प्रशासन चाहे तो मेरी गर्दन काट दे किंतु मैं अपने संकल्प पर दृढ़ हूं। विधायक कबीर के द्वारा इस प्रकार की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित वहां की सरकार भी नाराज है और उनकी पार्टी भी किंतु हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।विधायक कबीर की जिद के कारण मुर्शिदाबाद का सांप्रदायिक वातावरण पूर्णत: खराब होने की संभावना है और साथ ही देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए उक्त विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उसकी विधानसभा से सदस्य भी समाप्त कर देनी चाहिए। उक्त बात कहते हुए शिक्षाविद् रमेशचन्द्र चन्द्रे ने कहा कि भले ही भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है किंतु बाबर यहां पर आक्रमणकारी के रूप में आया था इसलिए उसके किसी नाम से मस्जिद का निर्माण करना यह देशद्रोह है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई अथवा बौद्ध होश् कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि टीएमसी ने उक्त विधायक को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है किंतु यदि पश्चिम बंगाल की सरकार उक्त विधायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है तो देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, साथ ही श्री चन्द्रे ने यह भी कहा कि देशभर के राष्ट्रभक्त संगठनों को उक्त विधायक हुमायूं कबीर की कठोर निंदा करना चाहिए तथा इसके निर्णय का सर्वत्र विरोध भी करना चाहिए।

जिले में शुरू हुआ 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान

मंदसौर। भारत को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान में विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जिला प्रशासन और सभी विभागों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया है। संगठन लंबे समय से जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य उन कारणों और परिस्थितियों को समाप्त करना है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि स्पष्ट नीतियों और लगातार हो रहे प्रयासों से भारत तेजी से बाल विवाह मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पंचायत, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को अभियान में सक्रिय सहभागिता के निर्देश दिए हैं। संगठन के प्रतिनिधि राम रघुवंशी ने जिला प्रशासन के सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'पूरे जिले में मिल–जुलकर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि हम बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य से पहले ही देश को इस अपराध से मुक्त करना संभव है।

कोटक म्यूचुअल फंड एनुअल आउटलुक 2026

इंदौर. कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (कोटक म्यूचुअल फंड) ने अपना मार्केट आउटलुक 2026 जारी किया. इस रिपोर्ट में आने वाले साल में भारत की आर्थिक स्थिति और उन अहम निवेश थीम पर विस्तार से जानकारी दी गई है, जो वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं. रिपोर्ट में शेयर बाजार, फिक्स्ड इनकम और थीमेटिक सेक्टर्स में मौजूद अवसरों की बात की गई है, साथ ही वैश्विक व घरेलू ट्रेंड को समझने पर जोर दिया गया है, जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए. कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश शाह ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में इक्विटी से मिलने वाला रिटर्न कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी पर निर्भर रहेगा। उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां वित्त वर्ष 2027 में डबल डिजिट की मजबूत अर्निंग दिखाएंगी। इसी मजबूती के कारण विदेशी निवेशक भारत में निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी (तरलता) बनी रहेगी.

एक्स्ट्रामार्क्स ने स्कूलों में शुरू की एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस सुविधा

इंदौर. एक्स्ट्रामार्क्स एजुकेशन ने इंदौर में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की शुरुआत की घोषणा की. यह एक नई और अत्याधुनिक तकनीक है, जिसे शिक्षकों को सशक्त बनाने, विद्यार्थियों की सीखने की रुचि बढ़ाने और क्लासरूम्स को इंटेलीजेंट व सहयोगात्मक लर्निंग स्पेस में बदलने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के साथ, एक्स्ट्रामार्क्स देश की पहली ऐसी शिक्षा कंपनी बन गई है जिसने स्कूल इकोसिस्टम के हर स्तर पर एआई को सार्थक रूप से शामिल किया है, चाहे वह लेसन प्लानिंग हो, क्लासरूम टीचिंग हो, असेसमेंट हों या फिर आफ्टर–स्कूल लर्निंग. एक्स्ट्रामार्क्स एजुकेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, टेक्नोलॉजी चरनीता कौर ने कहा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के साथ, हम सिर्फ एक और एआई टूल नहीं ला रहे हैं, असल में हम क्लासरूम अनुभव को नए सिरे से गढ़ रहे हैं. यह इनोवेशन एआई की ताकत को सीधे शिक्षकों और विद्यार्थियों तक पहुँचाता है, जिससे बड़े स्तर पर व्यक्तिगत, रोचक और सुरक्षित लर्निंग का माहौल तैयार होता है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को आईपीओ के लिए मंजूरी

इंदौर. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को पूँजी बाजार नियामक सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से इसके इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है. कंपनी ने 8 जुलाई, 2025 को सेबी के पास अपने आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे. यह आईपीओ प्रमोटर– प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में होगा. डीआरएचपी जमा करने की तारीख तक कंपनी का सब्सक्राइब्ड और पेड–अप शेयर कैपिटल 17,652,090 इक्विटी शेयर था। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है। प्रस्तावित बोनस इश्यू पूरा होने के बाद कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड–अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपए फेस वैल्यू वाले 176,520,900 इक्विटी शेयरों से बढ़कर 1 रुपए फेस वैल्यू वाले 494,258,520 इक्विटी शेयर हो जाएगी. प्रस्तावित बोनस इश्यू होने के बाद (यदि होता है), तो प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले शेयरों की संख्या अधिकतम 49,425,852 इक्विटी शेयर होगी। हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए ही रहेगी।

महिंद्रा ट्रैक्टर्स बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी में

इंदौर. महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपनी 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर श्रृंखला की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश में कृषि और ढुलाई से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच, किसान अधिक मज़बूती और उत्पादन क्षमता के लिये 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर अपना रहे हैं. महिंद्रा के 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर विभिन्न फसलों के लिये विशेष उपकरणों के बढ़ते उपयोग के बीच, छोटे और बड़े दोनों तरह के खेतों के लिये बेहद उपयुक्त हैं, विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां अलग–अलग तरह की मिट्टी पाई जाती हैय ये 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टर 20 से 70एचपी वर्ग की व्यापक श्रेणियों में उपलब्ध हैं. मध्य प्रदेश के अलावा, पूरे देश के किसान 4डब्ल्यूडी ट्रैक्टरों के फायदे महसूस कर रहे हैं और विश्व स्तर पर कृषि–प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने वाली इस प्रौद्योगिकी को तेज़ी से अपना रहे हैं. महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपनी विनिर्माण इकाइयों – नागपुर, मुंबई, ज़हीराबाद, रुद्रपुर, राजकोट और जयपुर– में अपने 4डब्ल्यूडी उत्पादों और समाधानों के विनिर्माण के ज़रिये इस खंड में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रही है.

टोयोटा हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ

इंदौर. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने प्रतिष्ठित हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान 'टोयोटा हॉर्नबिल म्यूज़िक फेस्टिवल 2025' का औपचारिक शुभारंभ किया. इस वर्ष के उद्घाटन समारोह की शुरुआत टोयोटा के ब्रांड एंबेसडर और विश्व–प्रसिद्ध जापानी ड्रम एंसेंबल ड्रम ताओ के विशेष प्रदर्शन से हुई, जिसने दर्शकों के बीच उत्साह, आनंद और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत माहौल बना दिया. टोयोटा हार्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल का उद्घाटन नागालैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ. फेस्टिवल से जुड़ाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तदाशी असाजुमा, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और लेक्सस, ने कहा हॉर्नबिल म्यूज़िक फेस्टिवल नागालैंड की वास्तविक आत्मा और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है. यह मंच राज्य की जीवंत परंपराओं, सृजनशीलता और विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम है.

निरूद्ध बंदियों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी

▸ जिला जेल में आयोजित हुआ तंबाकू मुक्त अभियान

मन्दसौर। तंबाकू मुक्त अभियान को लेकर जिला जेल मंदसौर में निरूद्ध बंदियों को भविष्य में तंबाकू का सेवन न करने हेतु आग्रह किया एवं तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला प्रेस क्लब संरक्षक ब्रजेश जोशी, जिला जेल अधीक्षक पीके सिंह, जेलर श्री राजेश कुमार, जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति सदस्य व मजदूर कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने जेल में निरूद्ध बंदियों को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि तम्बाकू, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू पान या अन्य रूप में हो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं प्रभावित करता, जिसने इसे अपनाया है, बल्कि उससे उसके परिवार, उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते है। तम्बाकू व्यसन एक ऐसी दलदल है, जो धीरे–धीरे हमारी सेहत, हमारी मानसिक शक्ति, और हमारी उम्मीदों को खोखला कर देता है। इसलिये अपने व अपने परिवार के लिये 'तम्बाकू–मुक्त' होने की प्रतिज्ञा ले।

इस अवसर पर मजदूर कल्याण समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धनलाल हाडा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा जोशी, जिला अध्यक्ष कमलनयन गुप्ता, प्रदेश महामंत्री बापू लाल गुर्जर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक भारतीय, जिला उपाध्यक्ष दशरथ यादव, रीना कहार, सहित जेल कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

साइबर क्राइम व बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम

▸ वन स्टॉप सेंटर एवं महिला–बाल विकास विभाग ने दी सेवाओं की जानकारी

मंदसौर। सीएम राइस स्कूल मल्हारगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, उड़ान संस्था, जनसाहस संस्था और वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में छात्रों को लैंगिक समानता, साइबर क्राइम, महिला हिंसा रोकथाम, बाल विवाह तथा वन स्टॉप सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।परियोजना अधिकारी संतोष शर्मा ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए सही उम्र में विवाह की आवश्यकता बताई। उड़ान संस्था की संगीता कुंभकार, ममता खींची और हरीश केसरिया ने लैंगिक समानता पर छात्रों से संवाद किया एवं महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों के सहयोग पर जोर दिया।जनसाहस संस्था की सिमरन नेकाड़ी ने साइबर क्राइम से बचाव और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। वन स्टॉप सेंटर से निर्मला चौहान ने पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली सहायता और केंद्र की सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक वाघेला, वाइस प्रिंसिपल मनीष गौड़ सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाध्यापक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई।

2019–20 की अतिवृष्टि से प्रभावित 15,186 किसानों का 27 करोड़ 47 लाख रूपए बकाया

▸ किसान हितैषी विधायक विपिन जैन ने विधानसभा में मामला उठाकर राहत राशी शीघ्र वितरण की मांग की

मन्दसौर। वर्ष 2019–20 में अतिवृष्टि के कारण मंदसौर जिले के किसानों की फसलों को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनज़र राहत राशि मंजूर हुई थी, उस समय कुल जिले में 80 करोड़ 8 लाख 46 हजार 518 रुपए की राहत स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 52 करोड़ 60 लाख 90 हजार 784 रुपए वितरित कर दिए गए थे, लेकिन विधानसभा क्षेत्र मंदसौर के जहाँ कुल 51,179 किसान प्रभावित थे उनमें से 15,186 किसान अब तक राहत राशि से वंचित रहे हैं। इन किसानों के लिए कुल 27 करोड़ 47 लाख 55 हजार 734 रुपए की शेष राशि बकाया है ।कई साल बीतने के बाद भी यह राशि उनके खातों में नहीं डाली गई।

किसान हितैषी विधायक विपिन जैन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया । उन्होंने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से तारांकित प्रश्न के माध्यम से अनुरोध किया कि शेष बकाया राशि शीघ्र स्वीकृत हो और प्रभावित किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाए । उन्होंने कहा कि उस समय राहत राशि व मुआवजा राशि के अन्य भाग बाद में स्वीकृत एवं वितरित हो चुके हैं इसलिए अब उन 15,186 किसानों को भी राहत राशि मिल जानी चाहिए।

प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि बकाया राशि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी ।

विधायक विपिन जैन ने आग्रह किया है कि प्रशासन एवं सरकार इस मांग पर संज्ञान लें और तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि 2019–20 में आपदा प्रभावित हुए किसान भी राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकें।

वरिष्ठ पत्रकार पारसमल लोढ़ा के देवलोकगमन पर लायंस क्लब के माध्यम से हुए नेत्रदान

मन्दसौर। वरिष्ठ पत्रकार पारसमल लोढ़ा के देवलोकगमन पर लोढ़ा परिवार द्वारा उनके नेत्रदान लायंस क्लब के माध्यम से कराये।

सकल जैन समाज के संयोजक सुरेंद्र लोढ़ा, गोशाला के अध्यक्ष संजय लोढ़ा, सतीश लोढ़ा, अजय लोढ़ा एवं सुधीर लोढ़ा की उपस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. किशोर शर्मा द्वारा नेत्र उत्सर्जित किये गये।

लायन अध्यक्ष रत्नेश कुदार, सचिव विक्रांत भावसार व प्रोजेक्ट चेयरमेन सीए विकास भंडारी ने इस कठिन समय में भी मानव सेवार्थ नेत्रदान के भाव जागृत करने पर लोढ़ा परिवार का आभार व्यक्त किया।

लायन अध्यक्ष रत्नेश कुदार, सचिव विक्रांत भावसार व प्रोजेक्ट चेयरमेन सीए विकास भंडारी, जगदीश चौधरी, भरत कोठारी, अजय धाकड़, आशीष मंडलोई, राजेश पोरवाल, सिद्धार्थ भंडारी ने उपस्थित होकर दिवंगत श्री पारसमल लोढ़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिजनों को उनके निर्णय के लिए साधुवाद ज्ञापित किया।

गौ तस्करी प्रकरण में एक आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

▸ अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ दी सजा, दो आरोपी दोषमुक्त

मंदसौर। सामान्य वनमंडल मन्दसौर के अंतर्गत वर्ष 2015 में दर्ज हुए गोह तस्करी प्रकरण में न्यायालय ने मुख्य आरोपी लालूनाथ पिता कालूनाथ निवासी पलवई को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वनमंडलाधिकारी श्री संजय रायखेरे ने बताया कि मामले में अन्य दो आरोपियों—पीरूनाथ पिता हरीसिंह एवं अर्जुननाथ पिता कालूनाथ—को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

वन विभाग के अनुसार, 18 जून 2015 को बीट बरदल कक्ष पी–06 पित्याखेड़ी मार्ग पर बीट गार्ड नरेंद्र मालवीय को गश्त के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। आवाज देने पर वे भागने लगे, जिनमें से लालूनाथ को मौके पर पकड़ा गया। उसके पास 5 जीवित गोह, एक सब्बल एवं मोटरसाइकिल क्रमांक स्क्र–14–स्स्र–5112 मिली, जिसे मौके पर ही जप्त कर लिया गया।

लालूनाथ से पूछताछ में उसके दो साथियों के नाम सामने आए, जिन्हें 23 जून 2015 को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग ने आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 17 अगस्त 2023 को लालूनाथ को दोषी करार दिया था। इसके विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा दायर अपील पर 27 नवंबर 2025 को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी तथा लालूनाथ की सजा को बरकरार रखा।

गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया

मंदसौर। वन मंडलाधिकारी मंदसौर संजय रायखेरे द्वारा बताया गया कि गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में विश्व चीता दिवस मनाया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीसागर नम्बर–03 के छात्र छात्राओं द्वारा चीता संरक्षण जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा चीता संरक्षण के संबंध में ''गांधीसागर हमारी शान –चीता हमारी पहचान जैसे नारे लगाये गये। कार्यक्रम में अधीक्षक गांधीसागर द्वारा गांधीसागर वन्?यजीव अभ?यारण?य में चीता पुर्नस्?थापना योजना की विस्?त्रत जानकारी दी गई। चीता प्रोजेक?ट से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। चीतों के पुर्नवास से गांधीसागर में पर्यटन में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी पश्चात चीता संरक्षण क्वीज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को पुरूस्कृत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में श्री पीएल रायकवार गेम रेंज अधिकारी पूर्व गांधीसागर एवं श्री पराग सेनानी गेम रेंज अधिकारी पश्चिम गांधीसागर एवं समस्त वन स्टॉफ उपस्थित रहा।

एक नजर ▸ एसडीएम बोले – प्रकरण जांच में, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जनजाति की जमीन की रजिस्ट्री

पीड़ित ने रजिस्ट्री निरस्त करने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

भानपुरा। केथुली ग्राम पंचायत के गुलाब नगर निवासी हरीसिंह पिता जोधराज भील (अनुसूचित जनजाति) ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला रजिस्ट्रार को पत्र एवं शपथपत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पैतृक सर्वे नंबर 619, रकबा 3.9020 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 1 हेक्टेयर भू–भाग की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर दी गई, जबकि यह भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग की है और ऐसी भूमि केवल कलेक्टर की अनुमति से ही बेची जा सकती है।

पीड़ित के अनुसार, उनके सगे काका ठाकुरसिंह पिता सोना भील भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, लेकिन दस्तावेजों में गलत तरीके से उन्हें सामान्य वर्ग दर्शाकर भूमि को रामबाबू पिता लालचंद निवासी नादियाखेड़ी, जिला झालावाड़ (राजस्थान) के नाम 10 अक्टूबर 2025 को बेच दिया गया। हरीसिंह ने आरोप लगाया कि विक्रेता के दो आधार कार्ड बने हैं—एक सामान्य वर्ग और दूसरा अनुसूचित जनजाति वर्ग का—और इसी आधार पर दस्तावेजों में हेराफेरी की गई।

फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप–शिकायत में हरीसिंह ने केलाश पिता गोरधन राणा (गुलाबनगर, केथुली) पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री के दस्तावेज केलाश राणा की ईमेल आईडी पर दर्ज हैं, जिससे उसकी संलिप्तता स्पष्ट होती है।

▸ **प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया**

नायब तहसीलदार ने बताया कि नामांतरण हेतु आई रजिस्ट्री में विक्रेता की जाति 'सामान्य वर्ग' दर्ज थी, जिस आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
एसडीएम राहुल चौहान ने कहा– 'प्रकरण मेरी जानकारी में आया है, जांच करवा रहा हूं। जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी।'
पटवारी प्रमोद मंडकरिया ने कहा कि नामांतरण से पहले रजिस्ट्री की जांच रजिस्ट्रार कार्यालय का दायित्व होता है।
जिला रजिस्ट्रार राजेश सोहित से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

▸ **पीड़ित की मांग**

हरीसिंह भील ने प्रशासन से मांग की है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन को सामान्य वर्ग बताकर की गई यह रजिस्ट्री अवैधानिक है, अत: इसे तत्काल निरस्त किया जाए तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करने व भूमि बिक्री कराने में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रकरण वर्तमान में जांचाधीन है।

उन्होंने कहा कि केलाश राणा स्वयं को 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद' का जिलाध्यक्ष बताकर प्रशासन को गुमराह करता है और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीनों की बिक्री करा रहा है।